

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
21.12.2022 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 2356 का उत्तर

बिहार में रेल नेटवर्क का विस्तार

2356. श्री छेदी पासवान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार में रेलवे नेटवर्क के सुधार और विस्तार के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;
- (ख) बिहार के जिलों में उक्त परियोजनाओं के लिए वर्तमान में आवंटित/जारी की जाने वाली प्रस्तावित राशि कितनी है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में रेलवे नेटवर्क के सुधार और विस्तार के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में नवनिर्मित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

बिहार में रेल नेटवर्क का विस्तार के संबंध में दिनांक 21.12.2022 को लोक सभा में श्री छेदी पासवान के अतारांकित प्रश्न संख्या 2356 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल अवसंरचना परियोजनाएं ज़ोनल रेलवे-वार स्वीकृत की जाती हैं न कि राज्य-वार/जिला-वार क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 66,597 करोड़ रुपये की लागत की 5,004 कि.मी. की कुल लंबाई वाली 52 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (32 नई लाइनें, 04 आमामान परिवर्तन और 16 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,240 कि.मी. को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 21,038 करोड़ का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

- 44,692 करोड़ रुपये की लागत की 2,875 किमी की कुल लंबाई वाली 32 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 435 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 22 तक 9,775 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
- 5,591 करोड़ रुपये की लागत की 849 किमी की कुल लंबाई वाली 4 आमामान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 682 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 22 तक 4,219 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
- 16,314 करोड़ रुपये की लागत की 1,280 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 16 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 122 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 22 तक 7,044 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

बिहार राज्य की परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर), पूर्व रेलवे (ईआर), पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) ज़ोनों द्वारा कवर किए जाते हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित परियोजना-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् [www.indianrailways.gov.in](http://www.indianrailways.gov.in) >Ministry of Railways> Railway Board> About Indian Railways> Railway Board Directorates>Finance (Budget)>Pink book

(year)> Railway-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme (RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

2014 से, बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है और उसके अनुरूप परियोजनाओं की कमीशनिंग हो रही है। बिहार राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों पर औसत वार्षिक बजट आवंटन को, 2009-14 के दौरान 1,132 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 3,061 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन की तुलना में 170% अधिक है। इन परियोजनाओं की वार्षिक बजट आवंटन को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2019-20 में 4,093 करोड़ रुपये (2009-14 के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन से 262% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 4,489 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 297% अधिक) और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5560 करोड़ रुपये तक (2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 391% अधिक) कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इन परियोजनाओं के लिए अब तक का सबसे अधिक 6,606 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय प्रदान किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट परिव्यय (1,132 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) से 484% अधिक है।

2014-22 के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1096 किमी लंबाई (317 किमी नई लाइनें, 425 किमी आमान परिवर्तन और 354 किमी दोहरीकरण) को 137 किमी/वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान कमीशनिंग (63.6 किमी/प्रति वर्ष) से 115% अधिक है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, बिहार राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 401 किमी खंडों (77 किमी नई लाइनें, 145 किमी आमान परिवर्तन और 179 किमी दोहरीकरण) को 134 किमी/वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग (63.6 किमी/वर्ष) से 111% अधिक है।

\*\*\*\*\*